No.F.1-1/8/2009(CPP-II)  

Registered  

All Universities

Subject: UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 7th July, 2009 on the above subject, I am enclosing a copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in educational institutions, 2009 published in the Gazette of India dt.4th July,2009 in (i) English and (ii) Hindi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रेरीन नियंत्रण से सम्बंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 for your information and necessary action.

The above regulations are mandatory and shall apply to all Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State/Union Territory Act and all Institutions recognised by or affiliated to such Universities and all Institutions deemed to be Universities under Section (3) of the UGC Act, 1956 with effect from 4th July, 2009 i.e. the date of its Publication in the official Gazette.

It is requested that these regulations may please be brought to the notice of the Colleges affiliated to your Universities/institution.

Yours faithfully,

(Dev Swarup)  
Joint Secretary

Encl: As above
Copy to:-

1. All States/ U.Ts Higher Education Secretaries (List attached).
2. The Secretary, Govt. of India Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3. Shri V. Umashankar, Director, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
4. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg (Kotla), New Delhi-110002
5. All Professional Councils.
6. Ps to Chairman/Ps to VC/Ps to Secretary, UGC, New Delhi
7. JS (Web site) UGC for posting on UGC website.
8. All Regional Offices, UGC.
9. Guard File

(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary
26.1.200
O/C
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक नियमों द्वारा जारी की गई विविध अवधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्बन्धित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2009

सं. 'एन'—15/13/14/8/2008—यो. व वि.---(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम---1950 के विनियम 95-क के
साथ जिति कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) हुआ प्रदान शक्तियों के अनुसार में
महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निर्देश की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य
बीमा निगम-1954 में निर्देश निर्धारित हिस्ताम तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकर्ता व्यक्तियों के परिवारों पर लागू
किए जाएगे अर्थात्

कोन्ना

उत्तमपाल्यम

जिला तेनी तालुक उत्तमपाल्यम के राजस्व गाँव

उत्तम पाल्यम तालुक जिला तेनी

उत्तमपाल्यम (मध्य), उत्तमपाल्यम (उत्तर), रायपुरमपोट्टी, मल्लंगुरुम, कोहिलागुरुम, कोम्ब (पूर्व), कोम्ब (पश्चिम) तथा हुनमालम पट्टी।

आद. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

1-139 01/2009
(3997)
दिनांक 10 जून 2009

स. एन-15/13/6/2008-यो. व. वि.- (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार में प्रदान किए गए 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के अनुसार विनियम का मानने के लिए है जिससे उक्त विनियम-95-क के तहत तिमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्देश चिकित्सा अस्तित्व में विनियमित क्षेत्रों में बीमारीक्षण व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएं, अर्थातः
केन्द्र
कंबम उत्तराखण्ड जिला लेनी

1. उत्तराखण्ड नगरपालिका क्षेत्र
2. उत्तराखण्ड जिला लेनी के राजस्व गैर
कायमकरणपद्धती, नारायणनैनपद्धती (दक्षिण), नारायणनैनपद्धती (उत्तर)
उत्तरपुरा और सी. पुडुपद्धती

आर. सी. शरमा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

'केन्द्र जिला के केंद्रानाल तहसील में गोरेंदुरु शिखर, जुड़ौटी, शिखर प्रसाद, श्रीसीतिहर्व एवं निमित्त के राजस्व गैर।'

आर. सी. शरमा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)
महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निर्देश दिए हैं जिससे उक्त विनियम–95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम–1954 में निर्दिष्ट विचित्रक्षा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाधिक्षता व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएँगे, अथाहत्

केंद्र

तुङ्किरिन जिला के पुडुक्कोट्टे क्षेत्र

1. मरप्पनपडू
2. कूलांडुगाडु
3. अल्लूरुपलम
4. कुम्बरगिरी
5. राजक बिलब्बकानपट्टी
6. सेनैक्कड़मपड
7. पेशेमी
8. सेनिलामण्णार आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान गाँव

आद. सी. नाम
संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 12 जून 2009

सं. एन–15/13/1/10/2008–यो. व. वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95–क के लायक पदक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा–46 (2) द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अनुसार में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निर्देश दिए हैं जिससे उक्त विनियम–95–क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम–1955 में निर्दिष्ट विचित्रक्षा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाधिक्षता व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएँगे, अथाहत्

'आन्ध्र प्रदेश राज्य के महाबलीपूर जिले के फालकसागर मण्डल में स्थित बेलजलू–1, 2, 3, और 'केंसरपेट्टा' मण्डल में स्थित 'पापरिखीपुड़ा' विभाग राजस्थान ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र.'

आद. सी. नाम
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन–15/13/14/7/2008–यो. व. वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95–क के लायक पदक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा–46 (2) द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अनुसार में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निर्देश दिए हैं जिससे उक्त विनियम–95–क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम–1954 में निर्दिष्ट विचित्रक्षा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाधिक्षता व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएँगे, अथाहत्

केंद्र

निम्नलिखित बड़े हुए क्षेत्र तेनी जिले के राजस्थान गाँव

1. उत्तमपालाथम तालुक का चिनमनपुर नरसागरीका क्षेत्र
2. उत्तमपालाथम तालुक जिले के राजस्थान गाँव, पूरानापौरपुरा, कलकुआनपौरपुरा, चिनालीपुरपुरा, पुरानापौरपुरा, राजस्थान क्षेत्र गाँव, कुस्तानपुर, ओलिपुरपुरा

आद. सी. नाम
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रेगिस्तान निर्देश से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जुन 2009

मिमोस 1-16/2007(सी.पी.पी.-II)

उद्देश्य

भारतीय उच्चतम न्यायालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एसएम.पी.10 सं 24295 , 2006 के 16-5-2007 तथा दिनांक 08-5-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगिस्तान निर्देश तथा रेगिस्तान रोकने के संकल्प की ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रा द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्घटनाहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में रहित करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कठिन, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुर्भाग्य पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करे। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपर्युक्त (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्लिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है—
1. शीर्षक, प्रारूप और प्रयोजन

1.1 ये अधिनियम "विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग के खिताब को रोकने के अधिनियम, 2009" कहे जाते हैं।

1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एक) के अनुसार /विश्वविद्यालय की परिसर के अन्तर्गत आनेवाली सभी संस्थानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीड्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के समवर्तित तत्त्वों से युक्त संस्थानों, विभागों, इकाईयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आयासीय, खेल के मैदान, जल्पान्ग गृह तथा विश्वविद्यालय, डीड्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बहार तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीड्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताडित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्योग तथा किसी नए आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य करना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का दर्शन इसके कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीड्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैंगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।
3. शैक्षणिक कौशल होती है—

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य शैक्षणिक के अन्तर्गत आएंगे—

क जिसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौलिक शब्दों अथवा स्थिरता कार्य उत्पीड़न अथवा दुर्योगिताकर करना।

ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पन्न करना अथवा अनुशासनीयता का वातावरण करना जिससे नए छात्र को कठिन, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ परिषद छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए रूकावट कार्य में बाधा पहुँचाए।

ड नए अथवा किसी अन्य छात्र को दूसरों को किया गया रूकावट कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च नए छात्र का किसी भी प्रकार से अधिक शोषण करना।

छ शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवाद करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कर्म जिससे किसी ब्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज मौलिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई--मेल, डाक, पत्रिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार नाम पर ले जाना, स्थानान्तरण अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आलविश्वास पर दुर्भावना पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार नाम पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।
4. परिणामार्थ

1. इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।

2. अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।

3. शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।

4. रैगिंग विषय में इंपलाइन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।

5. आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

6. समिति (कॉसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियुक्त उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा आव.इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.), डेटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.), सेंट्रल एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.), दी इंडिया काउंसिल ऑफ एपरिकलर रिसर्च (आई.सी.ए.आर.) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) इत्यादि तथा राष्ट्रों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि।

7. जिला स्तरीय रैगिंग विषय में समिति का तात्पर्य जिला विद्यालय की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसिमा में गठित समिति है।

8. संस्थापत्ता का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीन्स विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्रारंभ सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।

9. "फ़ेस्टर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।
3 संस्था का ताल्पय वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विद्यालय हो दीवाल विद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय नहल की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संस्थ के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती है कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें क्रम सीमा तक उपाधि दी जाती ही र नातक/नातककर्ता तथा उच्चतर रत्न अथवा विद्यालय प्रमाण पत्र की।

4 एनएएसी. का ताल्पय आयोग द्वारा अधिनियम की 12(३) अनुसार स्थापित नेत्राल एनेडमिक एंड एक्टियाराण काउंसिल है।

5 राज्य स्तरीय मनिटरिंग सेल द का ताल्पय राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा में केंद्र सरकार की सलाह पर रैंगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।

6 रस्ता तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्वच्छ नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के समान्य खंड 1887 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैंगिंग निवेदन के उपाय—

कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केंद्र विभागों तक नहीं उसकी संग तक ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केंद्र, उसके बू-गृह चाहे वे मेनेजर, आवासीय खेल के में अथवा जल्दी अथवा आदि चाहे वे विद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, राजी प्रकार के परिवहन, या निजी संभी में रैंगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपार करें। रिपोर्ट होने पर रैंगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।

3 सभी संस्थाएं रैंगिंग के प्रचार, रैंगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्यवाही करें।

6. संस्था स्तर पर रैंगिंग स्टार के उपाय

3.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्न मानित करने करें।

क संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक दृश्य, श्रेणी अथवा प्रिंट मीडिया के छात्र को
प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रेगिस्तान पूर्वता निषेध है।
यदि कोई रेगिस्तान करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रेगिस्तान प्रचार के बड़वेंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

क्र
प्रवेश की प्रस्तुतिका के निर्देश पुलिस तथा विवरण पत्रिका चाही वे इलेक्ट्रॉनिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छाएं जाएं। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रेगिस्तान होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रेगिस्तान विरोधी लाभित के सदस्यों, रेगिस्तान विरोधी दस्तावेज़ के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नवर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छाएं जाएं।

जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहाँ विश्वविद्यालय यह निर्धारित कर ले कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खान्ड (२) और खान्ड (३) का अनुपालन करें।

घ
प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शास्त्र पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिंदी/अमेरिकी की जात किसी एक प्रार्थनिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अन्य भाषी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उससे किसी अधिनियम के नियमों के पड़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा यह रेगिस्तान निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषणा करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निकासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही यह रेगिस्तान संबंधी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा/होनी और यदि वह रेगिस्तान करने अथवा रेगिस्तान के पुष्पण के दौष्टी पाया/पाए गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निकासित रहे सीमित नहीं होगा।

ड
प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शास्त्र पत्र अंग्रेजी
और हिंदी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिंदी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्न हैं। अभियंता के माता-पिता अभिमुक्त की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैंगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैंगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को बो जानते हैं तथा इसके लिए निर्देशित दंड को जानते हैं। ये घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैंगिंग से संबंधित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैंगिंग के दुष्प्रभाव में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया हो तब उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक रोकने नहीं होगा।

प्रबन्ध हेतु प्राथमिक पत्र के साथ स्कूल लीविंग/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/प्रवास प्रमाण-पत्र/विशेष प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा समाजीक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नजर रख सके।

संस्था के/सरकार द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रारंभिक करने वाले छात्र को प्रारंभिक पत्र के साथ एक अतिरिक्त शाखा पत्र देना होगा।

शपथ पत्र पर उसके माता/पिता/अभिमुक्त के भी हस्ताक्षर होंगे।

किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व संस्था अध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अधिकारियों जैसे छात्रपति (वार्डन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता-पिता अभिमुक्त, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करे तथा रैंगिंग रोकने के उपरोक्त और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्प्रभाव करने वालों को विनियम कर दर्ज लिया करने पर विचार-विचार हेतु हेतु उसे सम्बोधित करे।

समुदाय विवेचन रूप से छात्रों को रैंगिंग के अनान्वित प्रामाण्य के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रैंगिंग से अवगत कराने हेतु बटेक पोस्टर (बरीबता से बहु:रूपी) निभाये विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विविध तथा अन्य नवनों के सूचना पद्धति पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर रत्नधारी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं उन्हें रैंगिंग का आधार किए
जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जाएँ।

अ संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रेगिंग रोकने के नियमों का प्रचार-प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिखा पाए जाने पर विना भेद-भाव एवं गर्व के दण्डित करने के नियम प्रचार करे।

ट संस्था हारा संचित व्यक्तियों को समझाया जाए तथा असुरक्षित स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था हारा परिसर में विश्व समय तथा शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रेगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रेगिंग विरोधी सचिव दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता दी जाए।

ठ संस्था अवकाश के समय को नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व रेगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नूकरण नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।

ठ संस्था के विभिन्न तंत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि।

ठ संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वज्ञान कर निवारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व रेगिंग नियम संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विविधता प्रबन्ध करें।

ण प्रत्येक संस्था अकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पहले पेशेवर काउंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।

त संस्थागत स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर ग्राहन किए गए छात्रबाहर तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा सकेंगे भवन के संबंध में विस्तृत जानकारी हैं। संस्थागत यह भी सुनिश्चित करें कि रेगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रेगिंग रोकने हेतु चौकी से रखें।

6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाएँ, जिसका नाम इस प्रकार है--

क रास्ता में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पत्रिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किसी से निर्देशन प्राप्त करना
है। इसमें विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नं° तथा पते भी दी जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरस्त संपर्क करें। इन विनियमों में संदर्भित रैगिंग विरोधी हैल्वलाइन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं° विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।

संस्था इन विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (र) में निर्देश दिए गए हैं। प्रबंधक को नए छात्रों को दी जानेवाली परिक्षा द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु कार्य करें।

इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (र) में निर्देशित परिक्षा द्वारा नए छात्रों को संस्था के बीमारी क्षेत्र स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताए जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करे चाहे उनके लिए उनके वारिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास के रूप में दूरभाष नं° रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दे दें।

इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (र) में निर्देशित परिक्षा में संस्था में गन्नाए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की लिधि की हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।

वरिष्ठ छात्रों के अने पर संस्था प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजित करें जिनका नाम — (i) समृद्ध स्वीकारात्मक प्रोग्राम और वरिष्ठ और कलिष्ठ छात्रों की कार्यस्थल प्रशिक्षण व्यावसायिक वातावरण के साथ खण्ड — 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करें (ii) नये और पुराने छात्रों को समृद्ध अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैगिंग विरोधी समिति सम्बोधित करें (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकारिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों का आयोजित की जाये (iv) छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो (2) कलिष्ठ सहयोगियों से जुड़े सामय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करें (v) जहाँ तक संयम हो सके संकाय-सदस्य हॉस्टल में उन्हें वाले छात्रों के साथ भोजन भी करे ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास
का भाव उत्पन्न हो।

च संस्था समुचित समितियों का गठन करें। कोई इच्छार्थवाद तथा कुछ वरिष्ठ छात्र इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुरू बनाने में सह्योग दे।

छ नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे शैक्षिक आदेश के मोही हों अथवा शैक्षिक आदेश होते हुए उन्होंने दोषी को देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी प्रयास सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।

ज संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे गृहों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग गृह के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उपचित सहायता करें।

झ इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि बांटनें को सह्योग देता तथा छात्रावास में आवश्यक निरीक्षण करते रहें। जहाँ संकाय सदस्य की अपने अधीन छात्रों की डायरी मेंटेन करें।

ञ नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जाये और जहाँ इस प्रकार की सुविधाएं न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करें कि नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों पर वार्तन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।

ट संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में शैक्षिक आदेश देने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबंध करें।

ठ नये छात्रों के माता-पिता/अभिमानियों का यह दायित्व होगा कि शैक्षिक से रामचंद्र संरचना संस्था-अभिम से प्रदान करें।

ं प्रस्तुत तत्वों के समस्त प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो। यह और उसके माता-पिता/अभिमानियों प्रवेश के समय निर्देशित राजपथ पत्र दे जाए। कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (डी) (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना। प्रत्येक शैक्षिक वर्ग में चाहिए।
प्रत्येक संस्था दिनियम (6.2) खण्ड -- एल के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शास्त्र पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखें। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखें ताकि जब आवश्यकता हो कमीशन अथवा कोई संवैधानिक अथवा संस्था अथवा समस्त संविधान संशोधन अथवा किसी अन्य रक्षा के लिए अथवा संघर्ष द्वारा उनें प्राप्त किया जा सके।

प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करने समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नहीं किया है तो उसका निर्धारण होती ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानी जाए और विशेष रूप से निजी खंड पर व्यक्ति किये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है।

आयोग शास्त्र पत्रों के आधार पर एक उचित आंकड़ा बनाये रखे जो प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया गया हो। इस प्रकार द आंकड़ा रेगिस्टर की शिकायतों तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही का रिकार्ड भी रखें।

आयोग द्वारा आंकड़ा गैर सरकारी निकाय जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो को उपलब्ध कराया जाये इससे आम जनता में विवाद तथा समिति के आदेश का अनुपलन न करने की सूचना दी जा सके।

प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को रेगिस्टर से सम्बन्धित विषय और जानकारी से सम्बन्धित पत्र में तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके श्रम बालक रेगिस्टर से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।
6.3 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।

6 के प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रेगिस्टर विरोधी समिति (एंटी रेगिस्टर कंटेस्ट) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थापक करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशस्तिन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटन संघ कार्य सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता में से प्रतिनिधित्व, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षण कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधित्व समितियों में से सीन के आधार पर इस समिति में स्थान प्राप्त दोनों हो।

6 रेगिस्टर विरोधी समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्राक्कलन तथा रेगिस्टर से व्यवस्थित शासन का अनुपालन कराए तथा रेगिस्टर विरोधी दल के रेगिस्टर रोकने संबंधी कार्यों को भी देखें।

ग प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रेगिस्टर विरोधी (एंटी रेगिस्टर रैकम्प) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थापक द्वारा नामित किया जाए। यह समिति नवजात रखने तथा हर समय पैटर्निंग और गतिविधि बनी रहने हेतु तैयार रहें।

रेगिस्टर विरोधी 'मल/रैकम्प' में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिस्थितियों में बहार के व्यक्ति नहीं होंगे।

घ रेगिस्टर विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रवास तथा रेगिस्टर की दृष्टि से संवेदनशील अथवा स्थानों का घटनाओं को औचक निरीक्षण करें।

ड रेगिस्टर विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थापन अथवा अन्य किसी संगठन सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिमान द्वारा सूचित की गई रेगिस्टर की घटना स्थल पर जाकर करे तथा घटना की रिपोर्ट संस्थापक समिति रेगिस्टर विरोधी समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्यरत हेतु सौंपे।

रेगिस्टर विरोधी दल इस प्रकार की जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करें तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रेगिस्टर के दोषी पाए जानेवाले
छात्र/छात्री तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।

6.3 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनिटर करने-वाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनिटर होना चाहिए।

छ प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करें जिसे रूपेंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दे। मॉनिटरिंग सेल संस्थापकों रूपांतरण समिति रूपेंग वितरकी समिति रूपेंग वितरकी दल से रूपेंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। यह सिलाधिकारी को अध्यक्षता में गठित/जनपद स्तरीय रूपेंग वितरकी समिति के सम्मुख में रहे।

ज मॉनिटरिंग सेल; संस्था द्वारा किए जा रहे रूपेंग वितरकी उपायों का भी मूल्यांकन करेंगी। माता-पिता/अभिभाषकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रूपेंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जाँच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उनकी मुख्य भूमिका होगी। रूपेंग वितरकी उपायों के कार्यन्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.4 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करें, जिनका नाम हो--

क प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते है, संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हो, जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्थतः नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रूपेंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कष्ट के बाहर काउंसलिंग और समंदर बनाये रखें। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।
ख वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरबाह्य तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय समर्पण किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रवास में रह रहे सभी छात्रों को हो।

ग संस्था द्वारा राईंग रोकने से समबिंत अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रवास में नियुक्त चुरास्कर्मी संबंधी वार्डनों के नियंत्रण में हो तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए।

घ इन गवियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ओ) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर कार्यसिलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्रों जो मिलने वाले जीवन की दैनिक वस्त्र धृष्ट रूप छात्रवास में रहने से समबिंत कार्यसिलिंग बढ़ाते हो उन्हें कॉर्सिलिंग करें। ऐसे कार्यसिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जायें।

ड संस्था रेगिंग दिशोंके उपाध्य का व्यापक कार्यसिलिंग सत्र, कार्यशाला, पैंटिंग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

च संस्था के संकार सदस्य उसका शिक्षापतर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक रामित नहीं है, सुरक्षा गार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करनेवाले कर्मचारियों को रेगिंग तथा उनके दुर्घटनामय क्रियात्मक संचेतना के लिए संबंधित विभागों में समर्पित किया जाए।

छ संस्था/शिक्षण एवं शिक्षापतर प्रत्येक कर्मचारी से संवदान पर रखे गए प्रत्येक अधिकार के अपूर्तिपर बातें वे कृतिक में कर्मचारी हो अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाइ वाले कर्मचारी हों सभी एक अनुश्रव ले कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रेगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्रिय अधिकारियों को देंगे।

ज संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रेगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुश्रव करने देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।
संस्था द्वारा कीटिक और मैस देने की कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों
अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में
कड़ी नज़र रखें तथा रैंगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुर्सत
संस्थाव्यक्ति रैंगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दे।

शिक्षा की किरदार भी स्तर की उपाधि देनेवाली संस्था यह देख ले कि उसके
पाठ्यक्रम में रैंगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की
रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैंगिंग की
संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिष्क विज्ञानस्तिमिंग के स्थिति से
निष्ठुरने का लंब आना चाहिए।

प्रथम वर्ष नए विद्यार्थियों की ओर हर पन्डह दिन में गुमनाम वेतनांत्य संरक्षण
कि जाए। यह देखने के लिए कि संस्था में रैंगिंग नहीं हो रही है। संरक्षण की
रूपरेखा संस्था स्वयं निर्मित करें। संस्था द्वारा छात्र को दिए जानेवाले
विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य
चरित्र और व्यवहार के अनुसार यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कपी रैंगिंग
संबंधी अपराध में संलग्न रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को
हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।

इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए
हैं। इसके साथ ही सभी कार्यों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों
सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है
उसका यह समूचे दायित्व होगा कि वह रैंगिंग की घटनाओं को रोके।

विश्वविद्यालय से अन्य संस्थाओं अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सच से
प्रारम्भिक तौर पर नहीं किए तक रैंगिंग के आदेश हो अनुपालन तथा रैंगिंग विरोधी
उपाधियों की जानकारी से सम्बंधित इन विनियमों के अधीन साताहिक रिपोर्ट उस
विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा जिसके द्वारा वह संस्था रिकॉनाइज़ की गई
हैं। उसे है।

प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति महादेव दिश्वविद्यालय तथा रैंगिंग की देखरेख
करनेवाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्डह दिन बाद राज्य सराय देख रेख करने
दाले सेल को दे।

7  संस्थापत्य हारा की जानेवाली कार्यवाही—
   I. रेखिंग विरोधी दल अथवा समस्तिक किसी के भी हारा रेखिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थापत्य तुरंत सुनिश्चित करें कि बया कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्थाय अभ्यर्थ उसके हारा अधिकृत रेखिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्त के 24 घंटे के भीतर प्राध्यात्मिक दर्ज कराए अथवा रेखिंग से समस्तिक विधि के अनुसार संस्थिति दे। रेखिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।
   II. रेखिंग हेतु उकसाना
   III. रेखिंग का आपराधिक तत्क्षण
   IV. रेखिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
   V. रेखिंग के समय जनता को बाधित करना
   VI. रेखिंग के हारा शालीनता और नैतिकता बंग करना
   VII. दरियर को चोट पहुँचाना
   VIII. गलत ढंग से रोकना
   IX. आपराधिक बल प्रयोग
   X. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
   XI. बलात्क ग्रहण
   XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
   XIII. सम्पत्ति से समबिध अपराध
   XIV. आपराधिक धमकी
   XV. मुसीबत में पैंसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
   XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
   XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
   XVIII. रेखिंग की परिभाषा से समबिध सभी अपराध
      रेखिंग की परिभाषा से समबिध सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है।
आयोग और परिषद के कर्त्तव्य एवं दायित्व

8. आयोग और परिषद के कर्त्तव्य एवं दायित्व

8.1 आयोग रेगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीर्ष सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा:

क आयोग घन निर्देशित करेगा तथा एक टॉल फ्री रेगिंग विरोधी सहायता ग्राहक बनाएगा जो 24 घंटे हृदय रहेगी जिसका छात्र रेगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के नियामक हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

ख रेगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरंत संस्थाध्यक्ष, छात्रवास के वार्डन सम्बन्धित विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बन्धित जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी की दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामाजिक जनता उसका विस्तारण करे।

ग संस्थाध्यक्ष को एंटी रेगिंग हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्यस्त कार्य करेगा इन विनियम के उपलब्ध (बी) के अनुसार करनी होगी।

घ छात्र अथवा किसी भी व्यक्ति को रेगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संस्था मोड़ाइल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की छात्रवास तथा परिसर, कक्षाएं, संगोष्ठी कक्ष पुस्तकालय आदि के अतिरिक्त सभी घरों पर प्रयोग की अनुमति के अतिरिक्त सभी घरों पर प्रयोग की अनुमति देगा।

ड रेगिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों संकाय के सदस्यों, रेगिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रेगिंग विरोधी दल, जिले के अधिकारियों, हॉस्टल के वार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, फोन नम्बर
तथा पते छात्री को उपलब्ध कराए जाएं ताकि आकर्षित में वे उनका प्रयोग कर सकें।

च आयोग छात्रों तथा उनके माता–पिता/अभिमान द्वारा दिये गए शायर्प पत्रों के आधार पर आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़ा रेकिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाइ के रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

छ आयोग इस आंकड़े को केंद्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संघटन को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियम के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

6.2 आयोग नियम के अनुसार निम्नलिखित कदम चुटाएगा--

ः आयोग संस्था इत्या यदि आयोग निर्धारित करेगा कि वह अपनी विक्रियाका में केंद्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य सरकार के मौलिक संगठन निर्देशों के अनुसार अनुपालन न करने की रियाज बढ़ेगी तथा इसके लिए उनके लिए उपलब्ध आयोग की जाएगी।

ख आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता–पिता/अभिमान से शायर्प पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

ग आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के युद्धदृष्टिकोण प्रमाण पत्र में एक साथ यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रेकिंग निषेध समस्त किसी विनियम एवं उपयोग का अनुपालन किया जा रहा है।

घ रेकिंग की किसी भी घटना का संस्था के रूप अथवा एनएचएसी. अथवा किसी अन्य संस्था से एप्सी द्वारा दी जाने वाले रेकिंग और मेकिंग पर पुनःभाव पढ़ सकता है।

ड आयोग उन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दे सकता है अथवा अधिनियम खण्ड 12 बी के लिए अर्थ मान सकता है। जहाँ रेकिंग की घटनाएं नहीं होंगी।

च जहाँ रेकिंग की घटनाएं नहीं होंगी। आयोग रेकिंग रोकने के लिए एक इंटर
रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही—

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दंड दिया जाएगा।

रैगिंग विरोधी समिति उद्धरित दंड के सम्बन्ध में उद्धरित विनिर्देश लेंगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दंड देता अपनी संस्थाति देगा।

रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दंड देने।

I. कक्षा में उपस्थित होने तथा रैगिंग की अधिकारियों से मिलने नहीं

II. छात्र/छात्रा अनुमलन तथा अन्य लाभों को रोकना/विध्वंस करना

III. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से विध्वंस करना

IV. परीक्षा पर रोकना

V. किसी प्राधिकृत, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से विध्वंस करना।

VI. छात्रावास से निषिद्धित करना
VII. प्रवेश रद्द करना

VIII. संस्था से 04 सालों तक के लिए लिए निधान करना।

IX. संस्था से निष्कासित और परिवर्तन स्वरूप किसी भी संस्था में निगमित अवधि तक निधान करना। जब रेगिंग करने अथवा रेगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

रेगिंग विशेष समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।

I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बंध संस्था होने पर कुलपति से।

II. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलपति से।

III. संसद के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय गहरव की संस्था विश्वविद्यालय से उसके चेयरमैन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार।

9.2 यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन / सम्बंध कोई संस्था (जो उसके विद्याम अथवा सम्बंध उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम नियम के अनुसार असफल रहती है तथा रेगिंग को प्रभावात्मक ढंग से रोकने में असफल रहता है तथा विश्वविद्यालय उस पर निम्नलिखित से कोई एक अध्याय किसी समूहकार दण्ड लगायेगा–

I. सम्बंध/रेस्कार्जन या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना

II. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में डिग्री अथवा डिप्लोमा भाग लेने से रोकना।

III. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान को वापस लेना, यदि कोई हो।

IV. विश्वविद्यालय द्वारा संसद के माध्यम से दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना

V. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाता कोई अन्य दण्ड

9.3 जहाँ मिलीक्षेत्र देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रेगिंग की सूचना देने में धीर बसती गई है। रेगिंग की सूचना देने में त्वसित कार्यवाही नही की है। रेगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नही की है। इन निर्देशिका के अनुसार आवश्यक कार्यवाही नही की है। रेगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के द्वितीय विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
यदि इस प्रकार की दीवा संस्थापक के स्तर पर हुई है तो संस्थापक की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी।

9.4 कोई भी संस्था जो शैक्षिक रोकने इन विनियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं करेगा अथवा दोषियों को दर्ज नहीं करता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्यवाही करेगा।

I. अधिनियम के खंड 12 बी के अनुसार दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।

II. दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।

III. आयोग द्वारा दी जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष आर्टिस्टेस प्रोग्राम हेतु तंत्र को अयोग घोषित करना।

IV. सामान्य जनता अध्यक्षों को समाचार पत्र, मीडिया, आयोग की बैठक अदा हारा यह बताना कि संस्था में लघुतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं है।

V. इस प्रकार की अन्य कार्यवाही करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दंशित करना जब तक कि वह शैक्षिक रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले।

अयोग द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्यवाही में सभी समितियों सहयोग देंगी।

(००. ००. २००९)

(००. आयोग की चीफ)
अन्यथा का शपथ प्रमाणपत्र

1. अन्यथा/छात्र का धोखणा पत्र में पुजा/पुजी.................................................................

2. स्त्री/समूही/सुदी से रेगिस्तान द्वारा दिया गया टिकट तथा केंद्रीय/राज्य सरकार के इससे संबंधित निर्देशों का ध्यान से पढ़ा लिया है तथा पुर्यावत समझा लिया है। यौन संपर्क के लिए अनुमा में उपस्थित संस्थाओं में रेगिस्तान रोकने से सम्बंधित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान ले पढ़ा लिया है।

3. यौन संपर्क से रेगिस्तान 3 को पढ़ा लिया है समझा लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रेगिस्तान के रूप में काम नहीं करती।

4. मैं धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझा लिया है। अगर मैं किसी तरह के रेगिस्तान के लिए किसी को उकसाता हूँ तो किसी तरह के रेगिस्तान में भाग लेता हूँ। तो प्रशासन ने खिलाफ दंडानुक्रम कार्यवाही कर सकता है।

5. मैं निर्भयता पूर्व के शपथ करता हूँ कि मैं किसी की रेगिस्तान जो कि धारा 3 विनियम में उल्लिखित है उससे भाग नहीं लेंगा/लूंगी।

6. मैं किसी भी गतिविधियों में रेगिस्तान 3 विनियम के अंतर्गत नहीं।

मैं दिन नहीं लूंगा/लूंगी और प्राकार को रेगिस्तान के प्राप्त करता हूँ।

मैं यह जानता/जानती हूँ कि अगर मैं रेगिस्तान के मानले में अपराधी पाया गया/पाया गया तो मैं आपसी विनियम 9.1 के अनुसार दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा कानूनी प्रवृत्ति के अंतर्गत त्रस्तविधियों में जल्दी दंडानुक्रम कार्यवाही कर सकता है।

मैं यह जानता/जानती हूँ कि ने प्राप्त देश की किसी भी संस्था द्वारा रेगिस्तान नामक नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रश्न निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर..........................दिन..................नाम..............हस्ताक्षर..................

अमिताभी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

गरे द्वारा सत्यता पत्र के प्रविष्ट गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सत्य है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही बताया है न ही गलत बताया दिया है।

सत्यप्रवर्ती......................................................दिन..................नाम..............हस्ताक्षर..................

अन्यथा ने इसमें उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरांत शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

7-139 GI/2009
सलनक --I
मता--पिता/अभिमानक का शपथ प्रमाण--पत्र

1. मैं_________________________ पिता/माता/अभिमानक ____________

.........ने शेयरिंग निशेध के विधि तथा उच्चतम व्यापार के निर्देश को अनेकीय/राज्य सरकारों
के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में
शेयरिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम-2009 को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्वतथा समझ
लिया है।

2. मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती
हूँ कि शेयरिंग को कम माने हैं।

3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर में किसी तरह की शेयरिंग के
लिए किसी को उकसाता हूँ तो किसी तरह की शेयरिंग में भाग लेता हूँ, तो प्रशासन मेरे
खिलाफ ददात्राक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निरचत पूर्वक यह इक्विटी कहा कि
क) मैं किसी तरह की शेयरिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लिखित है उसमें भाग
नहीं लेनेगा/लेनेगी।
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लंबौला/लंबौली जो कि शेयरिंग के धारा 3 विनियम के
अंतर्गत आती है।

5. मैं यह दर्शाता/करता हूँ कि अगर में शेयरिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया
गयी हो, तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा
कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में भी, प्रतिबन्ध ददात्राक कार्यवाही की
जा सकती है।

6. मैं यह दर्शाता/करता हूँ कि मेरे विकृत देश की किसी भी संख्या द्वारा शेयरिंग मामले
में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरे प्रदेश निरस्त किया जा
सकता है।

हस्ताक्षर ________________________ दिन...... गहीना ......... वर्ष.........

हस्ताक्षर
नाम, पता, दूरभाष न.

शापथ प्रमाण--पत्र

मेरे ह्या सत्यप्रचार को वफादार पाया गया कि शापथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई
न कोई तथ्य गलत है। शापथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।
सत्यप्रचार............. दिन............. गहीना............. वर्ष.............

अन्यत्र ने हमारी उपविधि में शापथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरात्त शरीर को स्वीकार किता
तथा हस्ताक्षर किए।

शापथ आयुक्त
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th June 2009

No. N-15/13/14/8/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees’ State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre
Uthamapalayam Uthamapalayam Taluk, Theni District.

Areas Comprising the Revenue Villages of Theni District

Revenue Villages of Uthamapalayam (South), Uthamapalayam (North), Theni District, Rayappanpatti, Mallingapuram, Kohilapuram, Kombai (East), Kombai (West) and Hammanthan Patterson of Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P & D)

The 10th June 2009

No. N-15/13/14/6/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees’ State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre
Cumbum Uthamapalayam Taluk

Areas Comprising the following Areas Revenue Villages of Theni District

2. Revenue villages of Kamarayakoundentattiy, Narayanathevanpatti (South), Narayanathevanpatti (North) Uthamapuram and C. Pudupatti of Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P & D)

No. N-15/13/14/2/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees’ State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre
Karaikudi Sub-Urbs Devakottai Taluk, Sivagangai District

Areas Comprising the Revenue Villages of Perattukottai

R. C. SHARMA
Joint Director (P & D)

No. N-15/13/10/2/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950, the director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees’ State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely:—
"The Revenue villages of Narendraapur, Sibapur, Kurunti, Khadaga Prasad, Tulasiadiha & Nimidha Under the Tahsil of Dhenkanal in the District of Dhenkanal in the State of Orissa."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/10/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre
Pudukkottai area
Districr

Areas Comprising the following Revenue Villages of the District:—
1. Maravanmadam
2. Kootadunkadu
3. Alilikarn
4. Kuma.nagiri
5. South Silukkanapatti
6. Servaikka lamadam
7. Perurani
8. Sethuvilampannai

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

The 12th June, 2009

No. N-15/13/1/10/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely:—

"All the areas falling within the limits of Revenue Villages of Veljerva-I, II, III of Farooq Nagar Mandal and Papireddyguda Keshampeta Mandal in Manaboobnagar District in Andhra Pradesh".

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/14/7/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre
Chinnamanur

Areas comprising the Revenue villages of
1. Chinnamanur Municipal Limits of Uthamapalayam Taluk.
2. The Revenue Villages of Poolamanthapuram, Karkunkatankulam, Chinnaveiligapuram, Muthalapuram, Markayankottai, Pulikuthi, Kutchanur, Odaipatti in Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.

(under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956)

New Delhi-110002, the 17th June 2009

F.1-16/2007(CPP-II)

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of
"University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of
2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009,
and in consideration of the determination of the Central Government and the University
Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including
any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an
act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any
other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students
which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise
fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student
to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the
effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as
to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or
without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or
superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education
institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development,
physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in
consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause-(g) of sub-section (1) of Section 26 of
the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby
makes the following Regulations, namely;

8—139 GI/2009
1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".
1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it
under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. **What constitutes Ragging.**- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;

b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;

c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;

d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;

e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.

f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;

g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;

h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;

i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student

with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.
4. Definitions.-

1) In these regulations unless the context otherwise requires,-
   a) "Act" means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
   b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of
      students in any course of study in the institution up to the completion of
      academic requirements for that particular year.
   c) "Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established under clause (a) of
      Regulation 8.1 of these Regulations.
   d) "Commission" means the University Grants Commission;
   e) "Council" means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of
      any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the
      relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical
      Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India
      (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural
      Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India
      (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council
      of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.
   f) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by
      the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and
      elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.
   g) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a
      deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation
      as the executive head of the institution or the college is referred.
   h) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who
      is undergoing his/her first year of study in such institution.
   i) "Institution" means a higher educational institution, including, but not limited
      to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution
      of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of
      such institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading
      to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or
      higher level) and/or to a university diploma.
j) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council established by
the Commission under section 12(c)(c) of the Act;
k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State
Government for the control and elimination of ragging in institutions within the
jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the
Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in
the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in
the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not
limited to, the departments, constituent units, colleges, centres of studies and all
its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether
located within the campus or outside, and in all means of transportation of
students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of
studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of
ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required
measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to
achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against
those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or
being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration
of students; namely,

a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audio-
visual or print or any other media, for admission of students to any course of
study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution,
and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any
other law for the time being in force and such action would include but is not
limited to debarment or expulsion of such student.

e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an
affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional
languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the
English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed
by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and
understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any
other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging
and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these
Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled
and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not
indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found
guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded
against under these Regulations or under any penal law or any other law for the
time being in force and such action would include but is not limited to debarment
or expulsion of his/her ward.

f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form
of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration
Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural
pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by
the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant,
if admitted, whose behaviour has been commented in such document.

g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or
seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution,
including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit
additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form
prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along
with his/her application.

h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head
of the Institution shall convene and address a meeting of various
functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students,
parents/guardians, faculty, district administration including the police, to discuss
the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be
taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

i) The institution shall, to make the community at large and the students in
particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the
institution towards those indulging in ragging, prominently display posters
depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the
provisions of these Regulations and also any other law for the time being in
force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice
Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places,
where students normally gather and at places, known to be vulnerable to
occurrences of ragging incidents.

j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law
prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's
resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.

k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all
locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable
places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these
Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd
hours during the first few months of the academic session.

m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new
academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters,
leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the
objectives of these Regulations.

n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction
arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any
special needs of any specific section of students, in place well in advance of the
beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this
Regulation.

o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional
counsellors before the commencement of the academic session, to be available
when required by the institution, for the purposes of offering counselling to
freshers and to other students after the commencement of the academic year.
p) The head of the Institution shall provide information to the local police and local
authorities, the details of every privately commercially managed hostels or
lodges used for residential purposes by students enrolled in the Institution and
the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall
ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take
the following steps, namely;

a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet
detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various
purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the
student to contact the concerned person at any time, if and when required, of
the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the
institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant
district and police authorities;

b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of
these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their
induction and orientation which promote efficient and effective means of
integrating them fully as students with those already admitted to the institution in
earlier years.

c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall
inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and
clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or
against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any
attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to
the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.

d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall
contain a calendar of events and activities laid down by the institution to
facilitate and complement familiarization of freshers with the academic
environment of the institution.
e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely: (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration. (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.

f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.

g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.

h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.
j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.

k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.

l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.

m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.

n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorised to do so.

o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.

p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.
The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

Every institution shall constitute the following bodies; namely,

a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non-Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.

b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.

e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution
or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the Institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of Institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the Institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.

h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the Institution.
6.4 Every institution shall take the following other measures, namely:

a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.

b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among all students residing in the hostel.

c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.

d) The professional counsellors referred to under clause (a) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.

e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.

f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.

g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards
and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.

i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.

j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross-check whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been
punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.

n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

b) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

c) The Vice Chancellor of each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

i. Abetment to ragging;
ii. Criminal conspiracy to rag;
iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;
iv. Public nuisance created during ragging;

v. Violation of decency and morals through ragging;

vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;

vii. Wrongful restraint;

viii. Wrongful confinement;

ix. Use of criminal force;

x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;

xi. Extortion;

xii. Criminal trespass;

xiii. Offences against property;

xiv. Criminal intimidation;

xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);

xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);

xvii. Physical or psychological humiliation;

xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. **Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils.**

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;
a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.

b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.

c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.

d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.

e) The Commission shall maintain an appropriate database to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.

f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non-compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorised by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;
a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.

b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.

c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures.

d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.

e) The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.

f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.

g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency
responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. **Administrative action in the event of ragging.**

9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed hereinunder:

a) The Anti-Ragging Committee of the Institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.

b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;

- i. Suspension from attending classes and academic privileges.
- ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.
- iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
- iv. Withholding results.
- v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- vi. Suspension/ expulsion from the hostel.
- viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters.
- ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

- i. In case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;
ii. In case of an order of a University, to its Chancellor.

iii. in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely;

i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.

ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University.

Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies.

iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any

iv. Withholding any grants channelised through the university to the institution.

v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faulty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faulty or staff.

Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary
action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under
the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention
of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps
to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish
perpetrators or incidents of ragging suitably, take one of more of the following
measures, namely;

i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of
the Act.

ii. Withholding any grant allocated.

iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance
under any of the general or special assistance programmes of the
Commission.

iv. Informing the general public, including potential candidates for admission,
through a notice displayed prominently in the newspapers or other
suitable media and posted on the website of the Commission, declaring
that the institution does not possess the minimum academic standards.

v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose
such other penalties as may be provided in the Act for such duration of
time as the institution complies with the provisions of these Regulations.

Provided that the action taken under this clause by the Commission against any
institution shall be shared with all Councils.

(Dr. R.K. Chauhan)
Secretary
ANNEXURE I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, ______ (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _______ having been admitted to _______ (name of the institution) _______ , have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the “Regulations”) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that
   a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
   b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ______ day of _______ month of _______ year.

________________________
Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ______ (place) ______ on this the ______ (day) ______ of ______ (month) ______ , ______ (year) ______ .

________________________
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ______ (day) ______ of ______ (month) ______ , ______ (year) ______ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER
ANNEXURE II

AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. ___________________________ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, ___________________________ (full name of student with admission/registration/enrolment number) ___________________________ , having been admitted to ___________________________ (name of the institution) ___________________________ , have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

   a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

   b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ______ day of ______ month of ______ year.

______________________________
Signature of deponent
Name:
Address:
Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ______ (place)____ on this the ______ (day) of ______ (month) , ______ (year)____.

______________________________
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ______ (day) of ______ (month) , ______ (year)____ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER
PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon’ble Supreme Court in the matter of “University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others” in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;
1. **Title, commencement and applicability.**

1.1 These regulations shall be called the “UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009”.

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. **Objectives.**

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it
under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. What constitutes Ragging.- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:
   a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
   b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
   c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
   d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
   e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
   f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
   g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
   h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
   i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student
with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.
4. Definitions.-

1) In these regulations unless the context otherwise requires,-
   a) “Act” means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
   b) “Academic year” means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
   c) “Anti-Ragging Helpline” means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations.
   d) “Commission” means the University Grants Commission;
   e) “Council” means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.
   f) “District Level Anti-Ragging Committee” means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.
   g) “Head of the institution” means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
   h) “Fresher” means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
   i) “Institution” means a higher educational institution including, but not limited to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of such institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma.
j) “NAAC” means the National Academic and Accreditation Council established by the Commission under section 12(ccc) of the Act;
k) “State Level Monitoring Cell” means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-
   a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centres of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

   b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6. Measures for prevention of ragging at the institution level.-
6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,
   a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audio-visual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution,
and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any
other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.

e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.

f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.

g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application.

h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students,
parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.

k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.

m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.

n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.

o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available
when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.

p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.

b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted to the institution in earlier years.

c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.

d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.
e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration. (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.

f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.

g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.

h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.
j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.

k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.

l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.

m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.

n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorised to do so.

o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.

p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.
q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.

b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.

e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution
or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.

h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.
6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;

a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.

b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among all students residing in the hostel.

c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.

d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.

e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.

f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.

g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards
and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.

i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.

j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross-check whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been
punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.

n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

p) The Vice Chancellor of each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. **Action to be taken by the Head of the institution.**- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

   i. Abetment to ragging;
   
   ii. Criminal conspiracy to rag;
   
   iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;
iv. Public nuisance created during ragging;
v. Violation of decency and morals through ragging;
vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
vii. Wrongful restraint;
viii. Wrongful confinement;
ix. Use of criminal force;
x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
xi. Extortion;
xii. Criminal trespass;
xiii. Offences against property;
xiv. Criminal intimidation;
xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
xvii. Physical or psychological humiliation;
xviii. All other offences following from the definition of “Ragging”.

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. **Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils.**

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;
a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.

b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.

c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.

d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.

e) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.

f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorised by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;
a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.

b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.

c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures.

d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.

e) The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.

f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.

g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency
responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. **Administrative action in the event of ragging.-**

9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed hereinunder:

a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.

b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;

i. Suspension from attending classes and academic privileges.

ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.

iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.

iv. Withholding results.

v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.

vi. Suspension/ expulsion from the hostel.

vii. Cancellation of admission.

viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters.

ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

   Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;
ii. in case of an order of a University, to its Chancellor.

iii. in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely:

i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.

ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University.

   Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies.

iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any

iv. Withholding any grants channelled through the university to the institution.

v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff.

   Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary
action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one of more of the following measures, namely;

i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act.

ii. Withholding any grant allocated.

iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission.

iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.

v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.

Provided that the action taken under this clause by the Commission against any institution shall be shared with all Councils.

(Dr. R.K. Chauhan)
Secretary

To,

The Assistant Controller,
Publication Division, Govt. of India,
Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation,
Civil Lines Delhi -110 054
ANNEXURE I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, ____________________________, having been admitted to ____________________________, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the “Regulations”) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that
   a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
   b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___ day of __________ month of ______ year.

________________
Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ____________________________ on this the ______(day)____ of ______(month)____, ______(year)____.

________________
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ______(day)____ of ______(month)____, ______(year)____ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER
I, Mr./Mrs./Ms. _____________________________________________________ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of , _______________ (full name of student with admission/registration/enrolment number) ___________, having been admitted to _______________ (name of the institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the “Regulations”), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that
   a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
   b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ___ day of __________ month of ______ year.

____________________
Signature of deponent
Name:
Address:
Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein. Verified at ______(place)______ on this the (day)___ of ___(month)__, ___(year)____.

____________________
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ___(day)___ of ___(month)__, ___(year)____ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER